POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

# ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जनवरी, 2018 मूल्य 50 पैसे

## आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

गुजरात चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की सरकार के लिए अलार्म बजा दिया है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस फिर से अपनी जड़ें जमा रही है। हाल ही पंचायतराज की 31 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी खासी बढ़त बनाई है। यह ही नहीं शहरी सरकार यानी नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे भी यही संकेत दे रहे हैं।

इधर प्रदेश की सरकार अपने शासन के चार साल पूरे होने का जश्न मना रही है। प्रदेश के सभी अखबार सरकार की चार साल की उपलब्धियों के बड़े-बड़े विज्ञापनों से अटे पड़े हैं। दूसरी ओर प्रदेश के कई जिलों में कम हुई बरसात और सूखे की वजह से अन्नदाता गंभीर संकट से जूझ रहा है।

खरीफ के बाद अब रबी की फसल पर भी संकट के बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ करने का वादा कागजों में दब कर रह गया। फसल बीमा योजना किसान को कोई फायदा नहीं दे पा रही। गांवों के लोग रोजगार के लिए शहरों में भटक रहे हैं। रिपोर्ट है कि खेतीहर मजदूर महिलाओं को नरेगा में भी काम नहीं मिल पा रहा।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

चिकित्सकों की हड़ताल के कारण मरीजों को बेइलाज लौटना पड़ा है। ऐसी अनगिनत समस्याओं से घिरे ग्रामीण समुदाय को पटरी पर लाने के लिए ग्रामीण सरकारी मशीनरी और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकार को समय रहते जनता से किए गए वादों को पूरा करने की ओर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

## माता-पिता की सेवा नहीं की तो होगी जेल

माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक जो अपनी निजी आय से अपना गुजारा चलाने में असमर्थ है, अपने बच्चों पर भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। इसके लिए 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' लागू है।

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हर माता-पिता व बुजुर्ग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने बच्चों से कानूनन मासिक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वे आवास, भोजन, कपड़े और चिकित्सा सम्बन्धी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए उनसे क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश में न्यायाधिकरण भी स्थापित किए गए हैं, जहां इन मामलों का यथा शीघ्र निपटारा होता है।
- अगर किसी ने उनसे सम्पत्ति हस्तान्तरित करवा ली है, तो सम्पत्ति पाने वाले को सम्पत्ति हस्तान्तरण करने वाले माता-पिता व बुजुर्गों की जरूरतों का पूरा खयाल रखना होगा। अगर सम्पत्ति पाने वाला इसमें असफल रहता है तो सम्पत्ति के हस्तान्तरण को फर्जी करार दिए जाने का प्रावधान है।
- अधिनियम के अनुसार माता-पिता व वृद्धजनों की सही सेवा व देखभाल नहीं करने वालों को अब तीन माह तक की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- राज्य सरकार को भी वृद्धजनों की न्यूनतम आर्थिक स्तर की जरूरतें पूरी करने लायक पेंशन निर्धारित करनी होगी और उनकी चिकित्सा के लिए साधनयुक्त चिकित्सा वार्ड स्थापित करेंगी।

## होटल को महंगा पड़ गया चाय पर टैक्स काटना

राजकोट में रैयाधार क्षेत्र निवासी मोहितराज राठौड़ ने होटल न्यू अंकुर के खिलाफ उपभोक्ता मंच में मामला दर्ज कराया। अपने परिवाद में उन्होंने मंच को बताया कि वह कार चालक है। वह कार से 4 जुलाई को राजकोट से जूनागढ़ जा रहे थे। इस दौरान वह हाईवे स्थित होटल न्यू अंकुर पर चाय पीने के लिए रुके और दो कप चाय का आर्डर दिया। होटल ने दो कप चाय के 50 रुपए वसूले, जिसमें 7 रुपए 63 पैसे टैक्स (जीएसटी) के रूप में शामिल किए गए थे। उन्होंने चाय पर लगाए गए इस टैक्स पर आपत्ति जताई और होटल संचालक से स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन होटल संचालक की ओर से उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः हारकर उन्होंने मंच में मामला दर्ज कराया है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने चाय पर जीएसटी टैक्स वसूलने को सेवा दोष करार दिया और होटल न्यू अंकुर के संचालक को निर्देश दिया कि वह टैक्स की रकम छह फीसदी ब्याज के साथ उपभोक्ता मोहितराज राठौड़ को वापस करे। इतना ही नहीं, मंच ने होटल संचालक को उन्हें मानसिक प्रताड़ना व परिवाद खर्च के एवज में 1500 रुपए भी अदा करने के आदेश दिए हैं।

## ग्रामीण महिलाएं जागरूक होकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ लें...

'कट्स' द्वारा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के तहत 18 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए रेखा व्यास, भाजपा जिलाध्यक्ष (महिला मोर्चा) ने कहा कि ग्रामीण महिलाएं जागरूक हों और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लें साथ ही पात्र लोगों का श्रमिक कार्ड बनवाने में उनकी मदद करें।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राशमी के उपखण्ड अधिकारी पंकज शर्मा ने कहा कि

ग्रामीण महिला उपभोक्ता बैंकिंग योजनाओं की ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें और अन्य महिलाओं तक उन योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी करें, ताकि गांव की महिलाएं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सके।

कार्यक्रम में बीआरकेजीबी बैंक के शाखा प्रबंधक तिवाड़ी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में बैंकिंग सेवाओं और लाभप्रद योजनाओं की जानकारी देते हुए बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।

बैंक ऑफ बड़ोदा भीलवाड़ा शाखा के एफ.एल.सी. कॉर्डिनेटर पी.आर. नाहर ने मुख्यवक्ता के रूप में संबोधित करते हुए सूक्ष्म बीमा योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में 'कट्स' जयपुर के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने परियोजना के उद्देश्यों और प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर सूचना व परामर्श समिति के भगवान लाल शर्मा व गोवर्धन लाल शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन 'कट्स' के मदन गिरी गोस्वामी ने किया। कार्यशाला में गंगरार क्षेत्र के 14 गांवों से 18 पुरुषों सहित 74 महिलाओं ने भाग लिया।

## मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं

राज्य सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले चार सालों के दौरान प्रदेश के विकास के किए गए कामों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की ।

इनमें सरकारी अस्पतालों में हृदय रोगियों को मुफ्त एंजियोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने, किसानों को साढ़े पांच फीसदी की दर से सस्ता कर्ज देने, सड़क हादसे में घायलों का 48 घंटे तक फ्री इलाज करने, सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 साल करने, शहीद सैनिकों के एक परिजन को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने जैसी कई घोषणाएं शामिल है।

## संपत्ति का ब्यौरा देना भूले मंत्री

वर्ष 2010 में केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय व राज्यों के मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल 31 अगस्त तक देना अनिवार्य किया था। लेकिन राज्य में अपनी सरकार के चार साल पूरे होने का जश्न मना रहे मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना भूल गए हैं।

महज दो मंत्रियों (उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी और राजस्व राज्य मंत्री अमराराम) ने ही अपनी संपत्ति और कारोबार की जानकारी दी है। शेष मंत्रियों सहित कई आईएएस अफसर भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं।

## बीमारियों की बड़ी वजह है कुपोषण

प्रदेश में होने वाली बीमारियों के पीछे सबसे बड़ी वजह कुपोषण है। करीब 20 फीसदी मौतें

कुपोषण से होने वाली बीमारियों से हो रही है। गौरतलब यह है कि वर्ष 1990 में भी कुपोषण बीमारियों का मुख्य कारण था और 26 साल बाद भी स्थिति यही है। महिलाएं और बच्चे इससे होने वाली बीमारियों से ज्यादा प्रभावित हैं। कुपोषण के मामले में केवल बिहार हमसे आगे है।

हाल ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा देश की सेहत की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में पहली बार राज्यों को भी शामिल किया गया। रिपोर्ट से राजस्थान के सेहत की पड़ताल करने पर यह सच्चाई सामने आई, जो बेहद चिंताजनक है।

## एक भी महिला समूह डिफाल्टर नहीं

राजस्थान में 18 जिलों के 4 लाख 80 हजार ग्रामीण महिलाओं ने समूह में एकत्र होकर खुद को सशक्त करने के साथ ही परिवार और गांव को आर्थिक मजबूती दी है। पिछले एक साल में 9826 महिला समूहों को ऋण दिया गया। गर्व की बात यह है कि इन समूहों में से एक भी समूह डिफाल्टर नहीं है।

इन समूहों को जितना ऋण बांटा जा रहा है उसकी 100 फीसदी राशि समय पर वापस जमा हो रही है। साथ ही समूह की करीब 74 फीसदी महिलाओं की आमदनी में इजाफा हुआ है। ऐसे में महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने में स्वयं सहायता समूह खासे मददगार साबित हो रहे हैं।

## बीमा कंपनियां मालामाल

किसानों का फसल बीमा करने वाली कंपनियां मालामाल हो रही हैं। कंपनियों ने वर्ष 2016-17 में रबी तथा खरीफ सीजन में किसानों से प्रीमियम के तौर पर 2406 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जबकि बड़े पैमाने पर फसल खराब होने के बावजूद 1066 करोड़ रुपए का क्लेम स्वीकृत किया गया ।

किसान हताश है, लेकिन कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया है। इसके अलावा सरकार की कई योजनाओं में कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है। किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। सरकार बनाते समय किसानों से लुभावने वादे करने वाली सरकार केवल तमाशा देखती रही।

## कौशल प्रशिक्षण से बढ़ेंगे रोजगार

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार का मानना है कि युवाओं के लिए शिक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी कौशल विकास है।

उन्होंने बताया कि कौशल प्रशिक्षण से युवा अपने पैरों पर खड़े होते हैं और खुद अपने रोजगार की राह चुनते हैं। सरकार ने पिछले चार सालों में खास काम किया है और 2 लाख 8 हजार से भी ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार मुहैया कराया है।

## प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना...

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं द्वारा पंजीयन, जांच, प्रसव व बच्चे का जन्म पंजीकरण करवाने पर अब सरकार पांच हजार रुपए देगी। नये साल की एक जनवरी से इस योजना को लागू किया गया है। योजना के तहत महिलाओं को यह लाभ पहले जीवित बच्चे पर ही मिलेगा।

महिलाएं केवल एक बार ही योजना का लाभ ले पाएंगी। तीन किस्तों में मिलने वाली इस राशि के लिए समेकित बाल विकास निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आवेदन करना होगा। लाभार्थियों को भुगतान खातों में किया जाएगा।

## किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न तरीकों से मदद के कार्य शुरू किए हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे कृषि क्षेत्र को लाभ होगा और उस क्षेत्र में आर्थिक संभावनाएं बढ़ेंगी। कृषि में उपयोगी खाद और बीज की लागत कम करने के साथ ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, बिजली, आवास और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में सुधार करने की कोशिश कर रही है, ताकि इससे किसानों को मदद मिल सके। साथ ही उनकी मदद के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी कवायद की जा रही है।

## घट रहा है उपभोक्ताओं का विश्वास

देश की अर्थव्यवस्था अजीब स्थिति से गुजर रही है। जहां देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं का विश्वास लगातार गिर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में 50 फीसदी से ज्यादा परिवारों ने मंहगाई बढ़ने की उम्मीद जताई है।

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 80 फीसदी उपभोक्ताओं ने माना है कि देश में खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। जबकि रोजगार और लोगों की आय में कमी दर्ज की जा रही है। सर्वे के मुताबिक सितंबर महीने के मुकाबले नवंबर में उपभोक्ता विश्वास का सूचकांक 95.5 से गिरकर 91.1 पर आ गया।

## सड़क सुरक्षा की अनूठी पहल...

सोजत शहर के बेरा चगोनिया गांव में आए बारातियों को दिया गया तोहफा जितना अनूठा है उतना ही काबिले तारीफ भी है। गांव के मुकनाराम ने अपनी दो नातिनों की शादी में बारातियों को बिदाई में हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा को लेकर वो संदेश दिया जो सरकारी महकमें आज तक नहीं दे सके।

शादी समारोह में दूल्हों सहित सभी बारातियों को हमेशा वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की शपथ भी दिलाई गई। छोटे से गांव में रहने वाले मुकनाराम की यह पहल बड़े शहरों व कस्बों के लिए एक नजीर बन सकती है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485